भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3027
गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

ज्वारीय ऊर्जा हेतु संभावनायुक्त क्षमतायुक्त स्थान

3027. श्री एस॰ ज्ञानतिरावियमः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ज्वारीय ऊर्जा और शोध कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर ले रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु सहित देश में ज्वारीय परियोजनाओं की स्थापना हेतु किसी संभावनायुक्त स्थानों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ज्वारीय ऊर्जा हेतु अगले पांच वर्षों के लिए की गई/किए जा रहे अनुमानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) जी, नहीं। 30 करोड़ रु. से लेकर 60 करोड़ रु. प्रति मेगावाट तक की उच्च पूंजी लागत के कारण ज्वारीय ऊर्जा का दोहन करने के पूर्व के प्रयास सफल नहीं हुए।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई द्वारा दिसम्बर, 2014 में क्रिसिल (क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लि.), रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्युसन्स लि. के सहयोग से कराए गए एक अध्ययन के अनुसार ज्वारीय ऊर्जा की अनुमानित संभाव्यता लगभग 12,455 मेगावाट है। अल्प/मध्यम ज्वारीय तरंग शक्ति के साथ संभाव्यता वाले क्षेत्र हैं- गुजरात में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु में पल्क की खाड़ी-मन्नार चैनल और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, दक्षिणी हल्दिया और सुंदरबन।

(ग) और (घ): अत्यधिक पूंजी लागत के कारण सरकार ने अगले 5 वर्षों में ज्वारीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की है।

*****